

प्रेषक,

पी०के० महान्ति,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लघु सिंचाई विभाग,  
उत्तराखण्ड।

लघु सिंचाई विभाग

देहरादून : दिनांक 06 दिसम्बर, 2007

विषय : वित्तीय वर्ष 2007 - 08 के लिए जिला योजना के अन्तर्गत आयोजनागत मदों में घनाबंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लघु सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2007-08 में जिला योजना के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि में से रु० 197.40 लाख (रुपये एक करोड़ सत्तानवे लाख चालीस हजार मात्र) जिसका विवरण संलग्नक में अंकित है, को लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आपके निर्वहन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- उपरोक्त की जा रही धनराशि का उपभोग शासनादेश सं० 1454/11-2007-14(05)/2005 दिनांक 06.12.2007 में निहित प्राविधानानुसार किया जायेगा।
- 2- सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के बिरुद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जिला योजना से सम्बन्धित कार्यों पर व्यय जिला अनुभवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय एवं इसके अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के अनुसार ही किया जाय।
- 3- धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यों के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
- 4- उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैंडर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समव-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
- 5- स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन/फॉट सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा। जिला योजना की फॉट जिला अनुभवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय के आधार पर की जाय।
- 6- जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

क्रमशः.....2

- 7- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण- पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
- 8- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 9- विभागीय कार्य करने से पूर्व लघु सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन मठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 10- त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का मार्च, 2008 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक की अनुदान सं०-20 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित उपलेखा शीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामों डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-342(P)/XXVII-4 /2007 दिनांक 06.11.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(पी० के० महन्ति)  
सचिव

संख्या- 1455 / 11-2007-03(13)/05, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 2- वित्त वित्त अनुभाग-4
- 3- श्री एम०एल० पन्त, अपर सचिव, वित्त, बजट, अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री।
- 6- अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 8- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

(एस० एस० टोलिया)  
अनु सचिव

